प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय श्री मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायाधीश.

दांडिक अपील क्रमांक:1943/1997

अपीलार्थी : हर प्रसाद मरावी

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : म.प्र. राज्य। (अब छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 को सूचीबद्ध करें I

हस्ता/-

मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय श्री मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायाधीश .

दांडिक अपील क्रमांक:1943/1997

अपीलार्थी: हर प्रसाद मरावी।

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : म.प्र. राज्य। (अब छ.ग.)

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उपस्थिति;

श्री भास्कर प्यासी , अपीलार्थी के अधिवक्ता।

सुश्री सुनीता जैन, राज्य की ओर से पैनल अधिवक्ता।

निर्णय

(19 अक्तूबर 2012 को पारित)

1. यह अपील विशेष दांडिक प्रकरण क्रमांक 8/94 में प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश के आदेश दिनांक 11 सितंबर, 1997 के विरूद्ध निर्देशित है, जिसके अंतर्गत अपीलार्थी को

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (2) के सहपठित धारा 7 और धारा 13 (1) (घ) के अंतर्गत अपराध करने का दोषी ठहराया गया है (संक्षेप में 1988 का अधिनियम) और 1988 के अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत 6 महीने के साधारण कारावास और 500/- रुपये के जुर्माने और 1988 के अधिनियम की धारा 13 (2) के सह पठित धारा 3 (1) (घ) के अंतर्गत 1 वर्ष के लिए साधारण कारावास . और 500/- रुपये से दण्डित किया दशा में तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा I

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. संक्षेप में कथन किया, अभियोजन पक्ष का प्रकरण यह है कि जब अपीलार्थी डिप्टी रेंजर के रूप में जटवा वनक्षेत्र में पदस्थ था और काम कर रहा था। जटगा वन क्षेत्र के डिप्टी रेंजर ने शिकायतकर्ता बाबूलाल के घर की तलाशी ली और कुछ लकड़ी के लट्ठे प्राप्त किया और शिकायतकर्ता और कई अन्य ग्रामीणों के विरुद्ध वन अपराध का प्रकरण पंजीबद्ध करने की धमकी देकर प्रत्येक शिकायतकर्ता और गांव के अन्य निवासियों से 400/- रुपये की मांग की। मांग के उत्तर में, शिकायतकर्ता ने 200/- रुपये देने की बात कही और अपीलकर्ता ने उसे 3.11.1992 को घूस के पैसे के साथ बुलाया। चूंकि शिकायतकर्ता घूस देने को तैयार नहीं था, इसलिए प्रदर्श पी-1 की शिकायत 2.11.1992 को बिलासपुर स्थित सतर्कता कार्यालय में दर्ज किया गया था। प्री ट्रैप कार्यवाही तैयार की गई जिसके अंतर्गत शिकायतकर्ता और पंच गवाहों की उपस्थिति में फिनोलफ्थीलीन पाउडर के साथ सोडियम कार्बोनेट की प्रतिक्रिया का प्रदर्शन किया गया, प्रत्येक 100/- रुपये के दो करेंसी नोट पर फिनोलफ्थीलीन पाउडर लगाया गया था। इसे अपीलार्थी को सौंपने के लिए शिकायतकर्ता-बाबूलाल को दिया गया था। करेंसी नोट की क्रम संख्या लिख ली गई

। प्री ट्रैप   कार्यवाही का पंचनामा प्रदर्श पी/2 के तैयार किया गया । अभियोजन पक्ष का आगे का प्रकरण यह है कि इसके बाद ट्रैप पार्टी के साथ अपीलार्थी के घर/कार्यालय में गई और आरोप है कि शिकायतकर्ता ने अपीलार्थी की मांग के अनुसार घूंस की राशि दी, जिसे स्वीकार कर लिया

गया और इसके तुरंत बाद ट्रैप पार्टी घर में पहुंची और सह-अभियुक्त छेदीलाल के मेमोरेंडम (प्रदर्श पी-4) पर, अपीलार्थी के घर के मंच से प्रदर्श .पी.-5 के जप्ति ज्ञापन के अंतर्गत करेंसी नोट जप्त किए गए। शिकायतकर्ता और अन्य साक्ष्यों के हाथ धुलवाए गए, जिन्हें एकत्र कर बोतलों में बंद कर दिया गया। करेंसी नोट भी जप्त किये गये I वन अपराध की तैयारी से संबंधित अभिलेख, जप्त किये गये। क्षेत्र-रक्षक छेदीलाल से वन अपराध की तैयारी से संबंधित अन्य सुसंगत प्रदर्श पी/1 के सांथ जप्त किये गये I अभिलेख भी पूर्व में अभिगृहित कर लिए गए। अपीलार्थी की ओर से प्रदर्श पी-7. में ट्रैप पंचनामा पी-8 तैयार किया गया I ट्रैप की कार्यवाही पूरी होने के पश्च्यात पूर्व में प्रथम सूचना प्रदर्श पी-21 द्वारा दर्ज किया गया था। हाँथ की धोवन, करेंसी नोट के धुली हुइ घोल वाली सीलबंद बोतलों को रासायनिक परीक्षण के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला को प्रदर्श पी/24 द्वारा भेजा गया था। जिसके उत्तर में विधि विज्ञान प्रयोगशाला प्रतिवेदन प्रदर्श. पी-25 प्राप्त हुआ। आदेश दिनांक 25.2.1994 (प्रदर्श. पी-26) द्वारा अभियोजन की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात और सामान्य अन्वेषण पूरी होने के पश्चात, अपीलार्थी और सह-अभियुक्त-छेदीलाल के विरूद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। अभियोग पत्र के आधार पर, अधीनस्थ न्यायालय ने याचिकाकर्ता और अन्य सहअभियुक्त छेदीलाल के विरुद्ध 15.12.1994 को अधिनियम 1988 की धारा 7 और धारा 13 (1) (घ) सहपठित धारा 13 (2) के अंतर्गत अपराध करने का आरोप लगाते हुए आरोप विरचित किया । अपीलार्थी और अन्य अभियुक्त ने निर्दोष होने का अभिवाक् किया उन पर विचारण चलाया गया. अपने प्रकरण को सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 12 साक्षियों का परीक्षण कराया I से पूछताछ की। अपीलार्थी और सह-अभियुक्तों से उनके विरुद्ध प्रस्तुत होने वाले अभियोगात्मक साक्ष्यों और परिस्थितियों के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत परीक्षण किया गया । अपीलार्थी ने अपराध करित करना अस्वीकार किया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

3.दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और दंडादेश के अंतर्गत, यद्यपि परीक्षण न्यायालय ने अन्य सह-अभियुक्त छेदीलाल को दोषमुक्त कर दिया, अपीलार्थी को अपराध करने का दोषी पाया गया और ऊपर वर्णित अनुसार दण्ड सुनाई गई, जिसके विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

4. दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश की शुद्धता और वैधता पर सवाल उठाते हुए, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की प्रस्तुति का मुख्य तर्क यह है कि अभियोजन पक्ष के पूरे प्रकरण को शिकायतकर्ता - बाबूलाल (अभियोजन साक्षी-1) के साक्ष्य ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है, जिन्होंने न्यायालय के सामने बहुत दृढ़तापूर्वक कहा है कि अपीलार्थी द्वारा कोई मांग नहीं उठाई गई थी और अन्वेषण भी किसी अन्य वन अधिकारी द्वारा की गई थी। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, शिकायतकर्ता-बाबूलाल ने अपीलकर्ता के विरूद्ध कुछ भी नहीं कहा है, अभियोजन का पूरा प्रकरण मांग के सम्बन्ध में अत्यधिक संदिग्ध हो जाता है। आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि यह है कि करेंसी नोट अपीलार्थी के आधिपत्य से प्राप्त नहीं हुए थे, लेकिन साक्ष्य से पता चलता है कि ट्रैप पार्टी ने अपीलार्थी के घर के किसी कोने से करेंसी नोट प्राप्त करने का दावा किया है, जो अभियोजन पक्ष के प्रकरण पर गंभीर संदेह उत्पन्न करता है। उन्होंने आगे तर्क किया कि अभियोजन पक्ष के साक्षी - सी. केरकेट्टा (अभियोजन साक्षी.2) का अधिकारपूर्वक कहना कि वह शिकायतकर्ता के साथ था और उसकी उपस्थिति में, अपीलार्थी द्वारा दूषित धन दिया गया और स्वीकार किया गया और पुनः सह-अभियुक्त छेदीलाल को सौंप दिया गया, विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि रामबहादुर (अभियोजन साक्षी -8) के अनुसार, यह केवल शिकायतकर्ता है, जो अपीलकर्ता के घर के अंदर गया था। आगे कथन यह है कि अपीलकर्ता

5. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन कि है। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि शिकायतकर्ता ने यह शिकायत प्रदर्श पी/1, प्रस्तुत किया था और शिकायतकर्ता ने शिकायत पर स्वंम के हस्ताक्षर करने की बात स्वीकार की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उन्होंने आगे कथन किया कि भले ही शिकायतकर्ता ने अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है, लेकिन पंच साक्ष्यों ने स्पष्ट रूप से बताया है कि शिकायतकर्ता सतर्कता कार्यालय में आया था और कहा था कि अपीलार्थी द्वारा द्वारा रिश्वत की मांग की गई थी। सी. केरकेट्टा (अभियोजन साक्षी-2), जो एक पंच साक्षी है, का साक्ष्य कि याचिकाकर्ता द्वारा रिश्वत की मांग और स्वीकृति को सिद्ध करता है। इसलिए, यह साबित करने के लिए पुख्ता सबूत मौजूद हैं कि अपीलकर्ता ने रिश्वत की मांग की और उसे स्वीकार किया। राज्य के विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि छेदीलाल द्वारा दिए गए ज्ञापन के आधार पर पुख्ता सबूतों से करेंसी नोटों की बरामदगी साबित हो चुकी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि करेंसी नोट अपीलकर्ता के घर के अंदर रखे गए थे

और वहीं से बरामद किए गए हैं। करेंसी नोट की स्वीकृति की पुष्टि रासायनिक प्रतिवेदन के दृढ़ साक्ष्यों से भी होती है, जिससे पता चलता है कि अपीलार्थी के हाथ धोवन में फीनॉलपेथेलिन के अंश हैं। इसलिए, अपीलकर्ता ने करेंसी नोट को संभाला और घूंस स्वीकार की। इसलिए, 1988 के अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत यह उपधारण की जा सकती है कि पैसा अवैध परितोषण के रूप में और किसी स्पष्टीकरण के अभाव में स्वीकार किया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा जो भी कहा गया हो, रिश्वत लेना पूरी तरह सिद्ध होता है। इसलिए, दोषसिद्धि और दंडादेश में कि अतः, अधिनियम की धारा 20 के तहत यह अनुमान लगाया जा सकता है कि धन को अवैध रिश्वत के रूप में स्वीकार किया गया था और अपीलकर्ता द्वारा किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण न दिए दंडादेश जाने के कारण, रिश्वत की स्वीकृति पूर्णतः सिद्ध हो जाती है। इसलिये, दोषसिद्धि और दंडादेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है I

6. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है और अभिलेखों का परिशीलन किया है I

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

7. सी.के. दामोदरन नायर विरूद्ध भारत सरकार[1], सर्वोच्च न्यायालय के पास भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5(1) (घ) [अब अधिनियम, 1988 की धारा [13 (1) (घ)] में प्रयुक्त शब्द "अभिप्राप्त" पर विचार करने का अवसर था, और यह माना गया था: (एससीसी पृष्ठ 483, पैरा 12)

12. "हालांकि, जहां तक अधिनियम की धारा 5(2) के सह पठित धारा 5(1)(घ) के अंतर्गत अपराध का संबंध है, स्थिति अलग होगी। ऐसे अपराध के लिए अभियोजन को यह सिद्ध करना होगा कि आरोपी ने भ्रष्ट या अवैध विधियों से या लोक सेवक के रूप में अपनी स्थिति का दुरुपयोग करके मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ 'अभिप्राप्त' किया और वह भी अधिनियम की धारा 4(1) के अंतर्गत अपराधों के सम्बन्ध वैधानिक अनुमान की सहायता के बिना, क्योंकि यह मात्र धारा 5(1) (क) और (ख) के अंतर्गत अपराधों - और ना की अधिनियम की धारा 5(1)(ग), (घ) या (ङ) के अंतर्गत। ”अभिप्राप्त”' का अर्थ है अनुरोध या प्रयास के परिणामस्वरूप (कुछ) सुरक्षित करना या प्राप्त करना (संक्षिप्पित ऑक्सफोर्ड शब्दकोष)। अभिप्राप्त के प्रकरण में पहल उस व्यक्ति में निहित होती है जो प्राप्त करता है और उस संदर्भ में उससे मांग या अनुरोध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 161 के अंतर्गत अपराध के विपरीत अधिनियम की धारा 5 (1) (घ) के अंतर्गत अपराध के लिए प्राथमिक आवश्यकता होगी, जैसा कि ऊपर देखा गया है, 'स्वीकृति' या “'अभिप्राप्ति” के प्रमाण द्वारा स्थापित किया जा सकता है। विधिक स्थिति अब यह नहीं रह गई है कि अधिनियम की धारा 13 (1) (घ) के अंतर्गत अपराध की प्राथमिक आवश्यकता लोक सेवक से किसी मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ की मांग या अनुरोध का प्रमाण है। दूसरे शब्दों में, किसी मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ के लिए लोक सेवक से मांग या अनुरोध के साक्ष्य के अभाव में, धारा 13 (1) (घ) के अंतर्गत अपराध को स्थापित नहीं माना जा सकता है।

[1] (1997) SCC 477

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

8. ए. सुबैर विरुद्ध केरल राज्य[2] के प्रकरण में अपने बाद के निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 7 और धारा 13 (1) (घ) की आवश्यक तत्त्वों की, निम्नानुसार जांच की:

13. "धारा 7 के आवश्यक तत्व हैं:

(i) यह कि, परितोषण स्वीकार करने वाला व्यक्ति लोक सेवक होना चाहिए;

(ii) यह कि, उसने स्वयं के लिए परितोषण स्वीकार करनी चाहिए और संतुष्टि किसी भी आधिकारिक कार्य को करने या न करने के लिए या अपने आधिकारिक कार्य के अभ्यास में किसी व्यक्ति के प्रति पक्षपात या प्रतिकूलता दिखाने या न दिखाने के लिए एक उद्येश या परितोष के रूप में होनी चाहिए।

14. जहां तक अधिनियम की धारा 13(1)(घ) का संबंध है, इसके आवश्यक तत्व हैं:

(i) यह कि वह एक लोक सेवक होना चाहिए;

(ii) यह कि उसे अपने पद का भ्रस्त या अवैध विधि से प्रयोग किया जाना चाहिए या अन्यथा उसका ऐसे लोक सेवक के रूप में दुरुपयोग किया जाना चाहिए, और

(iii) कि उसे कोई मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए अभिप्राप्त करना चाहिए।"

`इसलिए, स्थापित विधिक स्थिति और जो अब मान्य नहीं है, वह यह है कि अधिनियम की धारा 13 (1) (घ) के अंतर्गत अपराध की प्राथमिक आवश्यकता लोक सेवक से किसी मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ की मांग या अनुरोध का प्रमाण है। दूसरे शब्दों में, किसी मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ के लिए लोक सेवक से मांग या अनुरोध के साक्ष्य के अभाव में, धारा 13 (1) (घ) के अंतर्गत अपराध को स्थापित नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त सुस्थापित

[2] (2009) 6 SCC 587`

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विधिक स्थिति को अनेक निर्णयों में दोहराया गया है। इसलिए, कथित अपराध को सिद्ध करने के लिए आवश्यक अवयवों में से एक लोक सेवक द्वारा रिश्वत की मांग है।

9. कथित अपराध के घटकों के संबंध में उपरोक्त सुस्थापित विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मैं यह पता लगाने के लिए अभिलेख पर साक्ष्य की जांच करने के लिए अग्रसर होऊंगा कि क्या अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे, मांग को साबित करने में सक्षम है I

10. शिकायत (प्रदर्श पी-1) के अवलोकन से पता चलता है कि शिकायत में लिखा गया आरोप यह है कि अपीलकर्ता ने कर्मचारियों के साथ शिकायतकर्ता के घर के अन्दर तलाशी गई थी और लकड़ी के लठठे जप्त किये, यह आरोप लगाते हुए कि यह वन उपज की चोरी का प्रकरण था और 400/- रुपये की मांग न केवल शिकायतकर्ता से की गई थी, बल्कि अन्य ग्रामीणों - देवदयाल साहू, तेजीराम साहू और सहसराम साहू से भी की गई थी। आगे आरोप यह है कि उनमें से प्रत्येक से रिश्वत के रूप में 400/- रुपये की मांग की गई थी, जिसके उत्तर में, शिकायतकर्ता ने कहा कि शिकायतकर्ता सहित प्रत्येक ग्रामीण प्रति व्यक्ति 200/- रुपये का भुगतान करने के लिए सहमत हैं और अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता को 3.11.1992 को रिश्वत की रकम देने के लिए बुलाया। लेकिन, शिकायत में लिखी गई यह कहानी शिकायतकर्ता-बाबूलाल (अभियोजन साक्षी-1) द्वारा अपने साक्ष्य में बिल्कुल भी समर्थित नहीं है। यदि हम बाबूलाल (अभियोजन साक्षी-1.) के साक्ष्य को देखें, तो अभियोजन का पूरा प्रकरण, कि शिकायतकर्ता-बाबूलाल और अन्य ग्रामीणों के घर की अपीलार्थी द्वारा तलाशी ली गई थी और अपीलार्थी और अन्य ग्रामीणों से 400/- रुपये के रिश्वत की मांग की गई थी, पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। शिकायतकर्ता-बाबूलाल (अभियोजन साक्ष्य-!) ने अपने साक्ष्य के कंडिका -1 में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि उप. रेंजर पांडे ने घर में तलाशी की और उसके घर से 18 नग लकड़ी के लठ्ठे जप्त किये, उन्होंने कहा कि उन्हें 200/- रुपये का जुर्माना देना होगा, जिस पर शिकायतकर्ता ने मंगलवार को 200/- रुपये देने की तैयारी

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

की । इसके पश्चात वह एक मंगलदास के साथ सतर्कता कार्यालय गए थे। मंगलदास ने कहा कि वह उसे जुर्माना की राशि नहीं देने देगा और जपत की गई लकड़ी वापस ले लेगा। इसके बाद मंगलदास की ओर से शिकायत-पत्र बनाया गया । शिकायत (प्रदर्श पी-1) के अवलोकन करने से पता चलता है कि इसे मंगलदास ने बनवाया था I शिकायतकर्ता - बाबूलाल ने अपने साक्ष्य के कंडिका -2 में आगे कहा है कि वह अनपढ़ है और केवल अपने हस्ताक्षर कर सकता है। हालाँकि, शुरू में, उन्होंने कहा कि आवेदन तैयार करने के बाद, उसे पढ़ाया गया था और फिर उन्होंने अपने हस्ताक्षर किए, उसी सांस में, वह मुकर गए और गवाही दी कि मंगलदास ने सतर्कता कार्यालय में जमा करने से पहले उन्हें शिकायत नहीं पढ़ी थी। वह अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह कहकर स्पष्ट करता है कि उसने डिप्टी रंजेर पाण्डेय के विरुद्ध शिकायत की थी एवं अपीलार्थी के विरूद्ध विजिलेंस कार्यालय में कोई परिवाद प्रस्तुत नहीं की गयी। अपने साक्ष्य के कंडिका -4 में उन्होंने पुनः दोहराया है कि डिप्टी रेंजर-पांडेय ने गाँव आकर तलाशी ली I उन्होंने आगे बताया कि कार्यवाही के बाद, उन्होंने मंगलदास से पूछा कि अपीलार्थी हरप्रसाद कैसे शामिल था, जबकि उन्होंने उससे डिप्टी रेंजर पांडे के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करने के लिए कहा था। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि यदि मंगलदास ने शिकायत-पत्र को सतर्कता कार्यालय में जमा करने से पहले उसकी सामग्री (प्रदर्श. पी-1) को पढ़ा होता, तो शिकायतकर्ता ने न तो उस पर हस्ताक्षर किए होते और न ही अपीलार्थी के विरुद्ध किसी कार्रवाई का अनुरोध किया होता I उन्होंने इस सुझाव से इनकार किया है कि परिवाद (प्रदर्श पी-1) सतर्कता कार्यालय में उन्हें पढ़कर सुनाई गई थी और उसके बाद उन्होंने इसे हस्ताक्षर किया था। उन्होंने अपने साक्ष्य के कंडिका -5 में आगे बताया कि सतर्कता कार्यालय के जिन दो अधिकारियों ने पूछताछ की, उन्होंने उनसे यह नहीं पूछा कि क्या शिकायतकर्ता अपीलकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करने का इरादा रखता है।

11. शिकायतकर्ता द्वारा अपने साक्ष्य के कंडिका -7 में बताई गई बातों से अभियोजन की कहानी को और क्षति पहुंचा है, जिसमें उसने कहा है कि उसने सतर्कता अधिकारी से पूछा कि किसे रिश्वत

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

की राशि दी जानी चाहिए और अधिकारी ने उससे कहा कि वह जिसे चाहे उसे पैसे दे सकता है। इसके बाद, उसने अपीलार्थी की मेज पर करेंसी नोट रखे और फिर संकेत दिया। उन्होंने कहा है कि जटगा में कार्यवाही पूरी होने के बाद शिकायत की सामग्री (प्रदर्श पी-1) उन्हें पढ़कर सुनाई गई थी। यह भी कहा गया है कि जब जटगा में उसके हाथ धोए गए, तो रासायनिक घोल का रंग नहीं बदला। उन्होंने अपने साक्ष्य के कंडिका-8 में यह भी कहा है कि सतर्कता कार्यवाही समाप्त होने के बाद, मंगलदास ने उन्हें बताया कि शिकायत-पत्र (प्रदर्श .पी-1) में, याचिकाकर्ता के विरुद्ध शिकायत की गई थी और यहां तक कि जब सतर्कता अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जा रही थी, तब भी उन्हें नहीं पता था कि अपीलार्थी के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है और जब उन्हें मंगलदास द्वारा सूचित किया गया था, तभी उन्हें पता चला कि सतर्कता अधिकारियों ने अपीलार्थी के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी है। पैरा-9 में उन्होंने प्रदर्श पी-3 में बयान देने की बात से पूरी तरह इनकार किया है। उन्होंने विशेष रूप से इस सुझाव का खंडन किया है कि उन्होंने रिश्वत की रकम अपीलार्थी के हाथों में सौंप दी थी और आगे इस बात से भी अस्वीकार किया है कि अपीलार्थी ने इसके बाद उसे दीक्षित, क्षेत्र रक्षक के हाथों में स्थानांतरित कर दिया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि उन्होंने मेज पर पैसे रखे थे। अपनी गवाही के पैरा-11 में, उन्होंने फिर से दोहराया है कि उन्होंने मंगलदास को डिप्टी रेंजर- पांडे. के विरुद्ध शिकायत करने के लिए कहा था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. शिकायतकर्ता के साक्ष्य, जैसा कि उसने अपनी तर्क के कंडिका-13 में दिया है, इस कारण का सुझाव देता है कि क्यों मंगलदास ने अपीलार्थी को मिथ्या फंसाया। बाबूलाल द्वारा यह अभिव्यक्त किया गया है कि अपीलकर्ता ने मंगलदास के आधिपत्य से लकड़ी जप्त थी और जुर्माना भी अभिरोपित किया था, और इसलिए, अपीलकर्ता और मंगलदास के बीच शत्रुता थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि अपीलार्थी द्वारा किसी रिश्वत की मांग नहीं की गई थी और न ही कोई जप्ती की गई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा है कि जब वह ट्रैप पार्टी फन्दा दल के

साथ जटगा रेंज कार्यालय गये और जब डिप्टी रेंजर- पांडे नहीं मिले, तब सतर्कता अधिकारी ने कहा कि वे खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे और किसी तरह प्रकरण बनाने के लिए, शिकायतकर्ता बाबूलाल को सतर्कता अधिकारियों द्वारा अपीलार्थी को चिन्हित धन देने के लिए बाध्य किया गया था, जिसे वह देने को तत्पर नहीं था, लेकिन, विवशतावश उसे अपीलार्थी की मेज पर पैसा छोड़ना पड़ा। उसके बाद; क्या हुआ, उसे नहीं पता I

13. शिकायतकर्ता के उपरोक्त साक्ष्य अपीलार्थी के विरुद्ध अभियोजन की पूरी कहानी को अत्यधिक संदिग्ध बनाते हैं। याचिकाकर्ता को अनुचित फंसाने की संभावना से अस्वीकार नहीं किया जा सकता। राज्य के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि सी. केरकेट्टा (अ.सा .2), जो कि पंच साक्ष्य है, ने अपीलार्थी द्वारा रिश्वत स्वीकार करने के संबंध में अभियोजन पक्ष के प्रकरण का पूरी तरह से समर्थन किया है, इसलिए, मांग और स्वीकृति की कहानी पर विश्वास किया जाना चाहिए, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जहां शिकायत-कर्ता ने स्वयं अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया है, स्वीकृति के संबंध में पंच गवाहों के साक्ष्य पर रिश्वत की मांग को सिद्ध करने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता है। सी. केरकेट्टा (अभियोजन साक्षी.2) का यह साक्ष्य कि उनकी उपस्थिति में शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ता को रिश्वत की राशि सौंपी, विश्वसनीय नहीं कही जा सकती, क्योंकि इस प्रश्न पर शिकायत कर्ता ने अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया है, लेकिन उसका साक्ष्य पूरी तरह से अलग है। इसलिए, ऐसे प्रकरणों में जहां शिकायतकर्ता स्वयं अपीलार्थी के विरुद्ध मांग का कोई आरोप नहीं लगाता है, न ही यह कहता है कि उसने अपीलार्थी को दूषित करेंसी नोट सौंपा है, और न ही वह यह कहता है कि अपीलार्थी ने दूषित मुद्रा स्वीकार की है, केवल पंच साक्ष्यों के आधार पर, यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष अपने प्रकरण को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में सफल रहा है। इसके अतिरिक्त ,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यह कहानी कि पंच साक्षी - सी. केरकेट्टा (अभियोजन साक्षी.2) उस समय उपस्थित थे जब अपीलार्थी को करेंसी नोट सौंपे गए थे, संदिग्ध हो जाती है क्योंकि रामबहादुर (अभियोजन साक्षी .8) के संस्करण के अनुसार, यह शिकायतकर्ता ही है जो अकेले अपीलार्थी के घर गया था। सी. केरकेट्टा (अभियोजन साक्षी .2) को करेंसी नोट उनके तर्कों के कंडिका-17 में विशिष्ट सुझाव दिया गया है कि ग्राम- जटगा, उप. रेंजर-पांडेय कार्यालय में नहीं मिले और विभिन्न अभिलेख तैयार कर लिए गए।

14. शिकायत में नामित तीन व्यक्तियों (प्रदर्श पी-1) में से दो व्यक्तियों - तेजीलाल और देवदयाल की भी अभियोजन साक्षी.4 और अभियोजन साक्षी.5 के रूप में जांच की गई है। एक और ग्रामीण. अर्थात् उमाशंकर जयसवाल से भी अभियोजन साक्षियों में से एक के रूप में पूछताछ की गई है। तेजीलाल (अभियोजन साक्षी .4) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वन विभाग का एक पांडे उनके घर आया था और वन उपज की चोरी के संबंध में पूछताछ की थी, जिस पर पांडे द्वारा लकड़ी के लठ्ठे को हटा दिया गया था और पांडे ने कहा था कि 400/- रुपये का जुर्माना उन्हें जमा करना होगा। उन्होंने आगे बताया कि अगली तारीख पर, वह रेंज कार्यालय जटगा गए, जहां उन्होंने पांडे से मिले और कहा कि वह केवल 200/- रुपये दे सकते हैं, जिस पर पांडे सहमत हो गए। अपने साक्ष्य के कंडिका-3 में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अपीलार्थी से न तो कोई बातचीत हुई और न ही अपीलार्थी द्वारा कोई मांग की गई। कंडिका-4 में उन्होंने याचिकाकर्ता को शामिल करने और फंसाने वाला कथन देने से मना किया है। अपने तर्क के कंडिका-5 में, उन्होंने कहा कि उन्हें परिवादकर्ता-बाबूलाल ने सूचित किया था कि बाबूलाल ने पांडे, डिप्टी रेंजर के विरुद्ध कार्रवाही के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया था।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

15. देवदयाल (अभियोजन साक्षी.5) ने यह भी बताया कि अपीलकर्ता कभी भी उनके घर नहीं आया, न ही कोई लकड़ी जब्त की और न ही रिश्वत की कोई मांग की। उनका कहना है कि उन्होंने पुलिस को कोई कथन नहीं दिया, जिसके बाद उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया है। उमाशंकर जयसवाल (अभियोजन साक्षी-6) का कहना है कि वह याचिकाकर्ता को नहीं जानता है और न ही वन अधिकारियों द्वारा कोई वस्तु जप्त की गई है। अपनी तर्क के कंडिका-3 में उन्होंने दोहराया कि अपीलार्थी कभी उनके घर नहीं आया और न ही कोई सामान जप्त किया। उन्होंने बताया कि वन परिक्षेत्र-सेमरा के रेंजर उनके घर आए थे और वन परिक्षेत्र-सेमरा के रेंजर पांडे द्वारा कागजों पर उनके हस्ताक्षर लिए गए थे। इस प्रकार, अभियोजन की कहानी अत्यधिक संदिग्ध हो जाती है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

16. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने भी अपनी तर्क को पुष्ट करने के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला प्रतिवेदन पर पर्याप्त जोर दिया कि अपीलार्थी के घर से दूषित धन की बरामदगी और फिनोलप्टेलीन के सकारात्मक परीक्षण से साबित होता है कि अपीलार्थी ने करेंसी नोट को संभाला था और यह अपीलार्थी के विरूद्ध कथित अपराध को सिद्ध करने के लिए मांग, स्वीकृति और वसूली की श्रृंखला को पूरा करता है।

कम से कम कहने के लिए, जिस तरह से अपीलार्थी के विरुद्ध प्रकरण तैयार किया गया है और प्रत्यार्थी और अन्य साक्षियों, विशेष रूप से तेजीलाल (अभियोजन साक्षी .4), देवदयाल (अभियोजन साक्षी.5) और उमाशंकर जयसवाल (अभियोजन साक्षी.6) द्वारा जो बयान दिया गया है, उससे करेंसी नोट की बरामदगी का कोई महत्व नहीं लगाया जा सकता है।

17. यह साक्ष्य में आया है और राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इससे अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि यद्यपि अपीलार्थी को फंसाने के उद्देश्य से शिकायतकर्ता को दो करेंसी नोट दिए गए थे, कथित रूप से जप्त किए गए दो दूषित करेंसी नोट में से, एक करेंसी नोट की क्रम संख्या ट्रैप

पूर्व पंचनामा में लिखी गई संख्या से मेल खाती है। यह अभियोजन पक्ष की कहानी पर भी संदेह पैदा करता है। राज्य के विद्वान अधिवक्ता का तर्क यह है कि चूंकि इस बात के साक्ष्य हैं कि अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता से रिश्वत स्वीकार की थी, इसलिए 1988 के अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत वैधानिक उप- धारणा भी लागू होती है कि पैसा अवैध परितोषण के रूप में स्वीकार किया गया था, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

18. वी. वेंकट सुब्बाराव विरूद्ध प्रतिनिधित्व द्वारा पुलिस निरीक्षक, ए.पी.[3] के प्रकरण में यह यह माना गया है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 13 (1) (घ) के अंतर्गत आरोपों को सिद्ध करने के लिए, अभियोजन पक्ष की ओर से यह साबित करना अनिवार्य है कि अभियुक्त ने रिश्वत की कोई मांग की थी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत वैधानिक उपधारणा को तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता है जब तक कि अभियुक्त ने रिश्वत के लिए धन स्वीकार नहीं किया है और जब तक यह सिद्ध नहीं हो जाता कि कोई हेतुक या परितोष था जिसके लिए मांग की गई थी और रिश्वत की मांग साबित हुई है। टी. सुब्रमण्यम विरुद्ध टी.एन राज्य[4] के प्रकरण में यह माना गया है कि अवैध परितोषण के रूप में मांग और धन की स्वीकृति के साक्ष्य के अभाव में आरोपी द्वारा धन की प्राप्ति का सीता राम विरुद्ध राजस्थान राज्य[5] के प्रकरण में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जब आरोपी अपीलार्थी द्वारा शिकायतकर्ता से रिश्वत की मांग की कहानी सिद्ध नहीं हुई थी और यहां तक कि शिकायतकर्ता द्वारा धन की मांग की कहानी भी युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित नहीं की गई थी, तो आरोपी को दोषी ठहराने के लिए उपधारणा के नियम का सहारा नहीं लिया जा सकता कि पैसा रिश्वत के रूप में स्वीकार किया गया था। सूरजमल विरुद्ध राज्य (दिल्ली प्रशासन)[6] के प्रकरण में यह माना है कि रिश्वत लेने के मामले में, जिन परिस्थितियों में भुगतान किया गया है, उनसे अलग किए गए धन की केवल वसूली, आरोपी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[3] (2006) 13 SCC 305
[4] (2006) 1 SCC 401
[5] (1975) 2 SCC 227
[6] AIR 1979 SC 1408

को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं होगी, जब प्रकरण में ठोस साक्ष्य विश्वसनीय नहीं होंगे। जगदीश चंद्र मखीजा विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य[7] में यह माना गया है कि एक ट्रैप प्रकरण में जब मांग और प्रस्ताव की कहानी का प्रारंभिक भाग अविश्वसनीय पाया जाता है, तो शिकायतकर्ता के साक्ष्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

19. ए. सुबैर (पूर्वोक्त) के प्रकरण में, यह अवधारित किया गया है कि:

"विधिक स्थिति अब यह नहीं रह गई है कि अधिनियम की धारा 13(1) (घ) के अंतर्गत अपराध की प्राथमिक आवश्यकता लोक सेवक से मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ की मांग या अनुरोध का प्रमाण है। दूसरे शब्दों में, आर्थिक लाभ की किसी मूल्यवान वस्तु के लिए लोक सेवक से मांग या अनुरोध के प्रमाण के अभाव में, धारा 13 (1) (घ) के अंतर्गत अपराध को स्थापित नहीं माना जा सकता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"वर्तमान प्रकरण के तथ्यों में केवल 20/- रुपये और 5/- रुपये मूल्य के करेंसी नोटों की बरामदगी, अपने आप में रिश्वत की मांग और स्वीकृति का उचित या पर्याप्त साक्ष्य नहीं माना जा सकता है। जब अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों में न तो गुणवत्ता है और न ही विश्वसनीयता, तो ऐसे साक्ष्यों पर दोषसिद्धि हेतु भरोसा करना असुरक्षित होगा।"

20. सूरजमल (पूर्वोक्त) प्रकरण मे अपनाए गए दृष्टिकोण को केरल उच्च न्यायालय के सी. एम. गिरीश बाबू बनाम सीबीआई, कोचीन मामले में दोहराया गया, जिसमें यह माना गया कि जब प्रकरण में साक्ष्य विश्वसनीय न हो, तो केवल दूषित धन की बरामदगी और उसे भुगतान करने की परिस्थितियों का अलग-थलग होना आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है। केवल बरामदगी से ही आरोपी के विरुद्ध अभियोजन पक्ष के आरोप साबित नहीं हो सकते, जब तक कि

---

[7] 1990 M.P,L,J, 239

रिश्वत की मांग को साबित करने या यह दिखाने के लिए विश्वसनीय साक्ष्य न हो कि आरोपी ने स्वेच्छा से धन स्वीकार किया था।

21. परिणामस्वरूप, दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय और दण्ड का आदेश विधि के अनुसार स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। इसलिए इसे अपास्त किया है। अपीलार्थी को आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। चूँकि अपीलार्थी पहले से ही जमानत पर है, इसलिए उसे आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नंही है i जमानत बंधक उन्मोचित किये जाते हैं I

22. तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है I

हस्ता/-

मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By ---------------------------------- Ankita Shrivastava